ernment in allowing the Hotel and Restaurants' Association to cater for troops on the Railway Stations and at other resting places; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) No.

(b) Does not arise.

डीजल इंजनों से चलाई जाने वाली रेल गाड़ियां

1324. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री पाराशर :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अक्तूबर, 1965 से कितनी रेलगाड़ियों में डीजल इंजिनों का प्रयोग किया जा रहा है तथा इस समय कुल कितने डीजल इंजन चल रहे हैं;

(ख) इस समय देश में कितने कारखाने डीजल इंजनों का निर्माण कर रहे हैं तथा उन की उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ग) क्या इटारसी डीजल शैड बन कर तैयार हो गया है और यदि नहीं, तो इस के कब तक तैयार हो जाने की संभावना है; और

(घ) क्या इन डीजल इंजनों की क्षमता दूसरे इंजनों से अधिक होती है तथा अन्य रेलवे इंजनों की तुलना में इन में खर्च भी कम होता है और यदि हां, तो दोनों प्रकार के इंजनों की क्षमता तथा खर्चे में कितना अन्तर है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 1-10-1965 को लाइन पर डीजल रेल इंजनों की संख्या इस प्रकार थी :—

बड़ी लाइन	485
मीटर लाइन	174
छोटी लाइन	33
जोड़	692

पूर्व, दक्षिण-पूर्व, मध्य, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर और पूर्वोत्तर-सीमा रेलों में डीजल रेल इंजनों का इस्तेमाल मुख्यत: मालगाड़ियों को चलाने के लिये किया जाता है। 1-10-65 से कुछ डीजल रेल इंजन हवड़ा-मद्रास मेल और हवड़ा-कालका मेल (केवल हवड़ा और आसनसोल के बीच) में भी लगाये जा रहे हैं। दिल्ली क्षेत्र की कुछ उपनगरीय गाड़ियां भी डीजल रेल इंजन से चलायी जा रही हैं। कालका-शिमला और नेरल-माथेरान पहाड़ी खण्डों में सभी सवारी गाड़ियां भी डीजल रेल इंजन से चलायी जा रही हैं।

(ख) एक; वाराणसी डीजल रेल इंजन कारखाने में उत्पादन की ऐसी योजना बनायी गयी है ताकि उस में उत्तरोत्तर चौथी योजना के मध्य तक प्रति वर्ष लगभग 150 मानक डीजल रेल इंजन बनाने का लक्ष्य पूरा हो सके और उत्पादन में आगे विस्तार की संभावना भी बनी रहे।

(ग) जी नहीं। 1966 के मध्य तक कुछ अनिवार्य सुविधाओं की व्यवस्था हो जाने की संभावना है और आशा है कि शैड 1967 के अन्त तक बन कर तैयार हो जायेगा।

(घ) मानक भाप रेल इंजन की अपेक्षा मुख्य लाइन मानक के डीजल रेल इंजन की कर्षण-क्षमता अधिक होती है, लेकिन डीजल रेल इंजन की लागत भी अधिक आती है। डीजल और भाप रेल इंजनों द्वारा परिचालन की लागत विभिन्न बातों पर निर्भर करती है जैसे कि अपेक्षित लगी हुई रकम, परिचालन के स्थान पर सम्बन्धित [illegible]

लागत, प्रत्येक खण्ड की स्थिति और विशेषता, खास तौर पर उस के उतार-चढ़ाव, यातायात का घनत्व, यातायात का स्वरूप आदि । इसलिए विभिन्न खंडों पर उपर्युक्त बातों के आधार पर तुलनात्मक लागत अलग अलग आयेगी । हमारा अनुभव यह रहा है कि जिन खण्डों पर यातायात का घनत्व अधिक होता है, उन पर भाप रेल इंजन की तुलना में डीजल रेल इंजन से परिचालन सम्बन्धी महत्वपूर्ण लाभ तो होते ही हैं, साथ ही आमतौर पर लागत भी कम आती है ।

पूर्वोत्तर रेलवे में अपराध

1325. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे सुरक्षा दल को, विशेषकर पूर्वोत्तर रेलवे में, गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष चलती हुई गाड़ियों, माल गोदामों और स्टेशन यार्डों में होने वाले अपराधों को रोकने में कितनी सफलता मिली है; और

(ख) इस अभियान में कितना खर्च हुआ है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) और (ख) एक बयान नत्थी है जिस में आवश्यक सूचना दी गयी है । सभा पटल पर रखा गया है **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये सख्या एल० टी०-5248/65]**

उत्तर प्रदेश में उद्योग

1326. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने 1965 में उत्तर प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिये कितनी राशि मंजूर की है;

(ख) राज्य सरकार ने अब तक कितनी राशि खर्च की है ; और

(ग) इस अवधि कितनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई हैं

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) 1965-66 के लिए उद्योग और खनिज के लिये 645 लाख रु० का परिव्यय स्वीकार किया गया है जिस में 300 लाख रु० की राशि बड़े तथा मध्यम आकार के उद्योगों के लिए, 7.5 लाख रु० खनिज विकास कार्यक्रम के लिये तथा 337.5 लाख रु० ग्रामोद्योग और लघु उद्योगों के लिये है ।

(ख) और (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और उसे सदन की मेज पर रख दिया जायगा ।

उत्तर प्रदेश के लिये टीन और सीमेंट का नियतन

1327. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से टीन और सीमेंट के वर्तमान अभ्यंश में वृद्धि किये जाने की प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सीमेंट के त्रैमासिक कोटे को 175050 मी० टन से बढ़ा कर 3 लाख मी० टन करने के लिए कहा है । जनवरी-मार्च, 1965 के यह कोटा 1,47,300 मी० टन से बढ़ा कर 1,75,050 मी० टन किया गया था । देश में सीमेंट की सीमित उपलब्धता होने के कारण तथा विक्रेताओं के पास सीमेंट के भारी